

GST क्षतपूरत वियवस्था के बाद की चुनौतियाँ

यह एडिटरियल 30/05/2023 को 'हृद्वि बज़िनेसलाइन' में प्रकाशित **“States GST challenge”** लेख पर आधारित है। इसमें जीएसटी क्षतपूरत वियवस्था की समाप्त के बाद राज्यों के लिये उत्पन्न चुनौतियों के बारे में चर्चा की गई है।

प्रलिस के लिये:

[वस्तु एवं सेवा कर](#), [GST क्षतपूरत उपकर](#), [सहकारी संघवाद](#), [केंद्र-राज्य संबंध](#), [GST परिषद](#)

मेन्स के लिये:

GST क्षतपूरत वियवस्था समाप्त होने के बाद राज्यों के समक्ष चुनौतियाँ, इन चुनौतियों से निपटने के उपाय।

वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax- GST) ने भारत के कराधान परदृश्य में एक महत्त्वपूर्ण रूपांतरण का सूत्रपात किया है। हालाँकि आरंभ में कुछ वनिस्माता राज्यों ने संभावित राजस्व प्रभाव के बारे में चिंता जताई थी। इन आशंकाओं को दूर करने के लिये केंद्र ने राज्यों को जीएसटी के लागू होने के बाद पाँच वर्ष की अवधि के लिये जीएसटी क्षतपूरत उपकर (GST compensation cess) के माध्यम से राजस्व हानि के वडुद्ध सुरक्षा का आश्वासन दिया था।

यद्यपि महामारी के कारण कुछ राज्यों के राजस्व में गिरावट आई, केंद्र ने राज्यों को समर्थन देने की अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए उधारी के माध्यम से बकाया राशि को चुकाने में सफलता प्राप्त की।

इस क्षतपूरत उपकर को मार्च 2026 तक के लिये बढ़ाया गया था ताकि केंद्र केंद्रीय खजाने के माध्यम से राज्यों को वतिरति राशि की क्षतपूरत कर सके, हालाँकि राज्यों को वसितारति लेवी की आय से कोई हिससा प्राप्त नहीं होगा।

जीएसटी वियवस्था के बारे में राज्यों की क्या आशंकाएँ थीं?

- **राजस्व वतिरण के बारे में चिंताएँ:**
 - 'उत्पादक' (Producing) राज्य जीएसटी प्रणाली के तहत 'उपभोगकर्ता' (Consuming) राज्यों के समक्ष राजस्व की हानि उठाने को लेकर आशंकित थे।
 - उन्नत राज्य, जो अधिक वस्तुओं का उत्पादन करते थे और उन्हें कम विकसित राज्यों को बेचते थे, वे तुलनात्मक रूप से कम जीएसटी संग्रहण को लेकर चिंति थे।
- **कर दर निर्धारण में शक्ति की हानि:**
 - राज्यों ने जीएसटी का वरिध किया क्योंकि इसने पूरे देश में वस्तुओं एवं सेवाओं के लिये एक समान कर दर का प्रस्ताव किया था। इसका अभिप्राय यह था कि राज्य वभिन्न वस्तुओं पर कर की दरें निर्धारित करने का अधिकार खो देंगे, जो राजकोषीय संघवाद (fiscal federalism) को कमजोर करेगा और उनकी स्वायत्तता कम हो जाएगी।
- **राजस्व हानि का डर:**
 - पूर्ववर्ती कर वियवस्था से जीएसटी प्रणाली की ओर संक्रमण के दौरान राजस्व की संभावित हानि को लेकर राज्य चिंति थे। चूँकि 17 वदियमान अप्रत्यक्ष करों को एक में वलिय कर दिया गया था, यह सुनिश्चित करने के लिये राजस्व-तटस्थ (revenue-neutral) दर निर्धारित करना महत्त्वपूर्ण था कि पूर्व की तरह राजस्व की समान राशि एकत्र हो सके।
 - जीएसटी दर के त्रुटिपूर्ण निर्धारण से राजस्व संग्रह में कमी आ सकती थी, जिससे राजकोषीय चुनौतियाँ बढ़ सकती थीं।

वस्तु एवं सेवा कर क्या है?

- **वस्तु एवं सेवा कर** (Goods and Services Tax- GST) एक मूल्य-वर्द्धति कर (value-added tax) है जो घरेलू उपभोग के लिये बिक्री की जाने वाली अधिकांश वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाया जाता है। यह एक **गंतव्य-आधारित कर** (destination-based tax) है।
- जीएसटी 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 के लागू होने के बाद वर्ष 2017 से लागू हुआ।

- इसका भुगतान उपभोक्ताओं द्वारा किया जाता है, लेकिन यह वस्तुओं एवं सेवाओं की बिक्री करने वाले व्यवसायों द्वारा सरकार को प्रेषित किया जाता है।
- केंद्र और राज्य समान रूप से एक साझा आधार पर कर लगाते हैं। केंद्र द्वारा अधिपति जीएसटी को केंद्रीय जीएसटी (CGST) कहा जाता है और राज्यों द्वारा अधिपति जीएसटी को राज्य जीएसटी (SGST) कहा जाता है।

जीएसटी पर राज्य सहमत कैसे हुए?

जब उनकी चर्चाओं को संबोधित किया गया तो राज्य साथ आने पर सहमत हो गए। कई कारक थे जिन्होंने राज्यों की सहमति के निर्णय को प्रभावित किया:

- **राजस्व संग्रह की स्वायत्तता:**
 - एक महत्वपूर्ण कारक जिसने राज्यों को जीएसटी के लिये सहमत किया, यह प्रावधान था कि **उन्हें शराब और पेट्रोलियम उत्पादों से राजस्व प्राप्त पर नियंत्रण** बनाए रखने की अनुमति दी गई थी।
 - इन वस्तुओं को **जीएसटी ढाँचे से बाहर** रखा गया था, जिससे राज्यों को शराब पर उत्पाद शुल्क और पेट्रोलियम उत्पादों पर वैट (VAT) लगाने की स्वायत्तता प्राप्त हुई।
 - महामारी के दौरान यह स्वायत्तता महत्वपूर्ण सदिध हुई जब कर संग्रह में गिरावट आ गई थी।
- **राजस्व क्षतपूरति:**
 - राज्यों की राजस्व संबंधी चर्चाओं को संबोधित करने के लिये केंद्र सरकार ने **उन्हें पाँच वर्ष की अवधि के लिये 14% (वर्ष 2015-16 बेसलाइन पर आधारित) की वृद्धि दर से राजस्व की कमी के लिये क्षतपूरति** का आश्वासन दिया।
 - इस क्षतपूरति के वित्तपोषण के लिये **वलासति एवं हानिकारक वस्तुओं (luxury and sin goods) पर एक क्षतपूरति उपकर** लगाया गया।
- **जीएसटी परिषद में शामिल करना:**
 - जीएसटी परिषद के गठन ने राज्यों का समर्थन प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें **प्रत्येक राज्य और केंद्र के प्रतिनिधियों को शामिल** किया गया था।
 - जीएसटी परिषद जीएसटी से संबंधित सभी मामलों के लिये निर्णयकारी संस्था बन गई, जहाँ **सर्वसम्मति की कमी के मामले में तदान के प्रावधान** किये गए थे।
 - परिषद में **केंद्र सरकार के पास एक-तर्हिई मत** है, जबकि **राज्यों को सामूहिक रूप से दो-तर्हिई मत** सौंपे गए हैं। इस संरचना का उद्देश्य निर्णय लेने के मामले में एक **सहकारी एवं समावेशी दृष्टिकोण** सुनिश्चित करना है।

GST क्षतपूरति की समाप्त पर राज्य कौन-से कदम उठा सकते हैं?

सुनिश्चित राजस्व सुरक्षा के अभाव का अर्थ है कि राज्यों को अपनी वित्तीय क्षमता बढ़ाने के लिये वैकल्पिक रास्ते तलाशने होंगे। यह स्थिति अनुपालन सुनिश्चित करते हुए राजस्व संग्रह को अधिकतम करने हेतु सक्रिय उपायों की मांग करती है।

राजस्व उगाही की सीमिति शक्तियों से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिये राज्य नमिनलखिति रणनीतियों अपना सकते हैं:

- **कर विश्लेषकी का उपयोग करना:**
 - **व्यापक डेटा विश्लेषण** से अंतरदृष्टि प्राप्त करने के लिये राज्यों को कर विश्लेषकी रणनीतियों एवं प्रक्रियाओं को अपनाना चाहिये। राज्य **वभिन्न स्रोतों से एकत्र किये गए डेटा का लाभ उठाकर** सटीक राजस्व अनुमानों के आधार पर सूचना-संपन्न निर्णय ले सकते हैं।
- **अनुपालन नगिरानी को सुदृढ़ करना:**
 - राज्यों को सड़क परिवहन विभागों के डेटा के साथ **ई-वे बलि रिपोर्ट की क्रॉस-रेफरेंसिंग के माध्यम से माल आवाजाही से संबंधित सूचना का मलिन** करना चाहिये।
 - यह दृष्टिकोण **संभावित वसिंगतियों का पता लगाने** और गैर-अनुपालक करदाताओं की पहचान करने में मदद करता है। हालाँकि ऐसी तुलनाओं पर **निर्भरता विकपूर्ण ही** होनी चाहिये क्योंकि वभिन्न रिपोर्टिंग आवश्यकताओं से विधिताएँ भी उत्पन्न होती हैं।
- **गैर-अनुपालक करदाताओं के लिये अनुकूलति उपाय:**
 - राज्यों को **करदाताओं को जोखिम मूल्यांकन और वगित अनुपालन पृष्ठभूमि के आधार पर वर्गीकृत करना** चाहिये। करदाताओं को वर्गीकृत करके और प्रत्येक समूह के लिये विशिष्ट नीतित उपायों को लागू करके **प्रवर्तन कार्रवाइयों को प्रभावी ढंग से लक्षित किया जा सकता है**। सरकुलर ट्रेडिंग और धोखाधड़ीपूर्ण चालान जैसे मुद्दों से निपटने के लिये यह दृष्टिकोण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।
- **सेवा उद्योग पर ध्यान केंद्रित करना:**
 - चूँकि राज्य **सेवाओं पर जीएसटी** लगाने का अधिकार रखते हैं, उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में **सक्रिय सेवा उद्योग का आकलन करना चाहिये**।
 - सेवा-संबंधित लेन-देन के मूल्यांकन में क्षमता निर्माण एवं विशेषज्ञता **करदाता आधार को व्यापक बनाएगी और राजस्व संग्रह को बढ़ाएगी**।
 - राज्यों को जीएसटी ऑडिट करना चाहिये और व्यापार सुविधा कयोस्क एवं संलग्नता कार्यक्रमों के माध्यम से करदाताओं के बीच जागरूकता पैदा करनी चाहिये।

■ सहकारी संघवाद का संपोषण करना:

- राज्यों को सहकारी संघवाद की भावना से एक-दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिये। जीएसटी कानूनों के सदिधांतों का अनुपालन करके और अनावश्यक क्षेत्रीय विवादों से बचकर राज्य व्यापार हेतु अनुकूल वातावरण का निर्माण कर सकते हैं और करदाताओं के विश्वास को बढ़ा सकते हैं।
- यह दृष्टिकोण अनुपालन को प्रोत्साहित करेगा, राजस्व को बढ़ावा देगा और आर्थिक विकास को संवृद्ध करेगा।

नष्िकरष:

राज्यों को राजस्व सृजन की बदलती गतशीलता के अनुकूल बनना चाहिये। जबकि आरंभिक चर्चाओं को केंद्र द्वारा संबोधित किया गया था, अब राज्यों को स्वतंत्र रूप से राजस्व बढ़ाने और कर जाल को वसितृत करने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।

कर विश्लेषकी का लाभ उठाने, अनुपालन नगिरानी को सुदृढ़ करने, सेवा उद्योग पर ध्यान केंद्रित करने और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने जैसे सक्रिय उपायों को नयिोजति करके राज्य इन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर सकते हैं। राज्यों के लिये यह अनविर्य है कि वे एक ऐसे वातावरण का निर्माण करें जो कारोबार सुगमता (ease of doing business) को बढ़ावा दे और करदाताओं में विश्वास पैदा करे; इस प्रकार, सतत राजस्व वृद्धि और आर्थिक विकास को आगे बढ़ाए।

अभ्यास प्रश्न: जीएसटी कषतपूरत राज्यों के राजस्व में कमी को दूर करने का एक अल्पकालिक उपाय थी। इसका दीर्घकालीन समाधान क्या हो सकता है? चर्चा कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQs)

????????

प्रश्न. नमिनलखिति मर्दों पर वचिर कीजयि: (2018)

1. छलिका उतरे हुए अनाज़
2. मुरगी के अंडे पकाए हुए
3. संसाधति और डबिबाबंद मछली
4. वजिजापन सामग्री युक्त समाचार पत्र

उपरयुक्त मर्दों में से कौन-सी वसतु/वसतुएँ जीएसटी (वसतु एवं सेवा कर) के अंतरगत छूट प्राप्त है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1, 2 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (c)

प्रश्न. 'वसतु एवं सेवा कर (गुड्स एंड सर्वसिज़ टैक्स/GST)' के क्रयानवति कयि जाने का/के सर्वाधकि संभावति लाभ क्या है/हैं? (2017)

1. यह भारत में बहु-प्राधकिरणों द्वारा वसूल कयि जा रहे बहुल करों का स्थान लेगा और इस प्रकार एकल बाज़ार स्थापति करेगा।
2. यह भारत के 'चालू खाता घाटे' को प्रबलता से कम कर वदिशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने हेतु इसे सक्षम बनाएगा।
3. यह भारत की अर्थव्यवस्था की संवृद्धि और आकार को वृहद रूप से बढ़ाएगा और उसे नकिट भवषिय में चीन से आगे नकिलने में सक्षम बनाएगा।

नीचे दयि गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयि:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

????

प्रश्न. वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 के तर्काधार की व्याख्या कीजिये। कोविड-19 ने कैसे वस्तु एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति नधिको प्रभावित किया है और नए संघीय तनावों को उत्पन्न किया है? (2020)

प्रश्न. उन अप्रत्यक्ष करों को गनाइये जो भारत में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में सम्मिलित किये गए हैं। भारत में जुलाई 2017 से क्रयान्वति जीएसटी के राजस्व नहितार्थों पर भी टपिणी कीजिये। (2019)

प्रश्न. संविधान (101वाँ संशोधन) अधिनियम, 2016 की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिये। क्या आपको लगता है कि यह "करों के प्रपाती प्रभाव को दूर करने और वस्तुओं और सेवाओं के लिये सामान्य राष्ट्रीय बाजार प्रदान करने" हेतु पर्याप्त रूप से प्रभावी है? (2017)

प्रश्न. भारत में माल व सेवा कर (GST) प्रारंभ करने के मूलाधार की वविचना कीजिये। इस व्यवस्था को लागू करने में वलिंब के कारणों का समालोचनात्मक वर्णन कीजिये। (2013)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/challenges-post-gst-compensation-regime>

